दिनांक :- 07-05-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ० फारूक आज़म (अतिथि शिक्षक)

स्नातक :- द्वितीय खंड (इतिहास)

विषय :- प्रतिष्ठा इतिहास (कला)

एकाई :- चतुर्थ

पत्र :- चतुर्थ

अध्याय – चीन में पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रसार

फ्रांस ने चीन को युद्ध क्षतिपूर्ति देने के लिए ऋण दिया। इसके बदले चीन ने यह वादा किया था कि वह हैनान का द्वीप किसी अन्य राज्य को नहीं देगा। कुछ ही दिनों में फ्रांस ने चीन में अनेक सुविधाएँ प्राप्त कर ली। 10 अप्रैल 1898 को फ्रांस चीन समझौते के अनुसार (क) फ्रांस को तोंगकिन से युन्नान पूरतक रेलवे मार्ग बनाने की सुविधा प्रदान की गई (ख) फ्रांस को 99 वर्ष के पट्टे पर क्वांगचाऊ

नौसैनिक अड्डा व कोयला स्टेशन के रूप में दिया गया

(ग) नई प्रस्तावित चीन डाक सेवा में फ्रांसीसी ~~सलाहकार~~ सलाहकार नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया।

(घ) युन्नान, क्वांगसी और क्वांगतुंग के प्रदेशों में खान खोदने तथा अन्य प्रकार के आर्थिक संसाधनों को विकसित करने का अधिकार फ्रांस को दिया गया।

ब्रिटेन – चीन के सम्बंधों में ब्रिटेन की नीति मूलतः व्यापारिक थी। वह चीन की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने का ढोंग भी रच रहा था। जर्मनी रूस व फ्रांस की चीन में गतिविधियों पर वह कोई प्रभावशाली रोक भी नहीं लगा सका था। वस्तुतः वह भी चीन के बंटवारे में अपने हिस्से के लिए तैयार था। फरवरी 1848 में ब्रिटेन का व्यापार चीन से चलता था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता

हो गया। इसके अनुसार चीन ने वचन दिया।
(क) यांगत्सी नदी के आस-पास के प्रदेश किसी अन्य देश को नहीं देगा। (ख) जब तक ब्रिटेन का व्यापार चीन से चलता रहेगा तब तक चीनी सीमा शुल्क सेवा का महानिरीक्षक एक अँग्रेज ही रहेगा। (ग) जब तक पोर्ट आर्थर रूस के प्रभुत्व में रहेगा तब तक वे-हाई-वे का बन्दरगाह नौसैनिक अड्डे के रूप में ब्रिटेन के पास पट्टे पर रहेगा। (घ) हाँगकाँग के सामने के मुख्य महाद्वीप के पट्टे की अवधि बढ़ाई गई। नवम्बर 1898 तक ब्रिटिश सरकार को 2800 मील लम्बे नौ रेल मार्ग बनाने की सुविधा मिल गई।

जापान - पश्चिमी देशों के इस बन्दरगाह ने जापान को भी प्रोत्साहित किया और वह भी अपने लिए स्थान सुरक्षित कराने के प्रयास में पिल पड़ गया।

Scanned with CamScanner

इसने माँग की कि फारमोसा के निकट फुकिन प्रांत को किसी अन्य देश के प्रभाव क्षेत्र के रूप में प्रदान न किया जाय। चीन ने इसे मान लिया।

इटली-1870 तक इटली का एकीकरण हो गया था वह भी चीन की लूट में अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहता था उसने चीनी सरकार से अनुरोध किया कि सनसैन खाड़ी उसे पट्टे पर दे दी जाए। चीनी सरकार ने इस बार हिम्मत करके इन्कार कर दिया। इससे चीनी साम्राज्य की बन्दर-बाँट (concession grabbing) कुछ समय के लिए रुक गई।

अमरीका - संयुक्त द्वार नीति - चीनी साम्राज्य के बंदर बाँट में अमरीका शामिल नहीं हुआ। कारण यह था कि जिस समय चीन में लूट-खसोट चल रही थी। उस समय वह स्पेन से युद्ध में व्यस्त था।

अतः वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। साथ ही चीनी तरबूज के किसी टुकड़े को प्राप्त करने की उसकी उत्कट अभिलाषा भी नहीं थी। अमरीका तो प्रारंभ से ही परम मित्रराष्ट्र (Most Favoured Nation) का व्यवहार प्राप्त करने का इच्छुक था। किंतु यह तब होगा था वह भी चीन में अपना प्रभाव क्षेत्र चाहता था।

1898 में अमरीका ने स्पेन को पराजित कर फिलिपीन पर अधिकार कर लिया इसके बाद वह पूर्वी एशिया में अधिक दिलचस्पी लेने लगा। इसी समय 1898 में जॉन हे (John Hay) संयुक्त राज्य अमरीका का विदेश सचिव नियुक्त हुआ चीन में अमरीकी हितों की सुरक्षा के लिए उसने एक नई नीति का प्रतिपादन किया जिसे खुले द्वार की नीति (Open Door policy) कहते हैं। इस संबंध में उसने ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, जापान इटली तथा

को लिखा और उनसे मांग की कि वे चीन में अनुमुक्त

द्वार की नीति का अनुसरण करे। 6 सितम्बर 1899

को उन सरकारों के पास भेजे गए पत्र में कहा गया

सभी देश विधिवत आश्वासन दे तथा अन्य संबंधित

देशों से आश्वासन दिलाने में सहयोग प्रदान करे कि

(क) चीन के अनेक बन्दरगाहों में व्यापार के संबन्ध में जो

अधिकार संधियों को द्वारा विदेशी राज्यों को प्राप्त है

उनमे कोई अन्य राष्ट्र हस्तक्षेप नही करेगा, चाहे

वे बंदरगाह किसी भी विदेशी राज्यों के प्रभाव क्षेत्र में

हो अथवा पट्टे पर हो। (ख) अपने पट्टे पर लिए हुए

अथवा प्रभाव क्षेत्र के प्रदेश में जो आयात तथा निर्यात

की सीमा शुल्क दरे निर्धारित है, उनका सम्मान किया

जाए एवं तट कर की दरे सब देशों के लिए समान हो

जिसकी वसूली चीनी सरकार करें।

Scanned with CamScanner

(घ) पट्टे पर लिए गए बंदरगाहों में आने वाले विदेशी जहाजों से अपने जहाजों की अपेक्षा कोई भी देश अधिक बन्दरगाह खर्च न होगा। (ङ) अपने क्षेत्र की रेलों पर अन्य विदेशी व्यापारियों के माल पर उससे अधिक किराया नहीं लेगा जो कि वह अपने देश के नागरिकों से वसूल करता है वस्तुतः उपर्युक्त अनुमुक्त द्वार की नीति व्यावसायिक स्वार्थ की नीति थी। अमरीका इस नीति का प्रतिपादन कर चीन का द्वार सभी देशों को व्यापार के लिए खोलना चाहता था इसमें चीन की क्षेत्रीय अखंडता या उसकी राजनीतिक स्वतंत्र की कोई चर्चा नहीं थी इतिहासकार आर० आर० पामर ने ठीक ही कहा है। अनुमुक्त द्वार नीति चीन को चीनियों के लिए नहीं, अपितु सभी विदेशियों के लिए अनुमुक्त रखने की नीति के अनुसार यह तय हुआ कि चीन की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे।

Scanned with CamScanner